जनसत्ता

नाकामी का धुआं

दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की हालत जानलेवा होने की ओर बढ़ने के बावजूद इसके फिलहाल पहचाने गए कारणों से निपटने को लेकर संबंधित सरकारें जिस स्तर की अनदेखी बरत रही हैं, उससे यही लगता है कि उन्हें इस बेहद गंभीर संकट की कोई फिक्र नहीं है! खबरों के मुताबिक पंजाब में मंगलवार को खेतों में पराली जलाने की इस मौसम की सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं। वहां के किसानों ने पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद साढ़े छह हजार से ज्यादा जगहों पर अपने खेतों में पड़े फसल के अवशेषों के निपटान के लिए उनमें आग लगाई। नतीजतन, पिछले एक-दो दिनों में वायु की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ ही था कि इतने बड़े पैमाने पर पराली जलाने के बाद फिर उसके बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। यह स्थिति तब है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पराली जलाने और उसकी वजह से प्रदूषण पैदा करने वालों से किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं हो सकती। बुधवार को एक बार फिर शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप पूरी तरह नाकाम रहे हैं; अब समय आ गया है जब उन अधिकारियों को दंडित किया जाए, जिन्हें किसानों को पराली जलाने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी।

दरअसल, पिछले कुछ सालों में धान की फसल तैयार होने और उसके अवशेष के रूप में पराली से निजात पाने की अवधि जिस तरह बदली है, उससे उपजी समस्या पर गौर करने के बजाय सरकारों ने इसकी व्यापक अनदेखी की। अगर फसल तैयार होने और कटने का समय सिमटा है और हवा के बहाव की वजह से पराली जलाना अब एक बड़ी समस्या बन गया है तो इसकी पहचान और विश्लेषण कर इसके हल का रास्ता निकालना किसकी जवाबदेही है? किसानों के सामने विकल्पों का अभाव पराली जलाने को उनकी मजबूरी बनाता है तो क्या सरकार को किसी ठोस योजना पर काम नहीं करना चाहिए, ताकि इस मुश्किल का सामना आसानी से किया जा सके? सवाल है कि अगर कई सालों से समस्या की शक्ल कमोबेश एक ही तरह की बनी हुई है तो संबंधित राज्यों की सरकारों ने इसके हल के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए? आज अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने इन सरकारों को फटकार लगाने की नौबत आ गई है तो इसमें क्या अस्वाभाविक है?

सही है कि आमतौर पर हल साल इस मौसम में हवा में प्रदूषण की समस्या गहराती है और इसके कई कारक होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार पंजाब और हरियाणा में बड़े दायरे में खेतों में पड़े फसलों के अवशेषों के निपटान का कोई आसान विकल्प नहीं होने की वजह से वहां के किसान आग लगा कर उसे नष्ट करते हैं, ताकि नई फसल के लिए खेत खाली हो सकें। लेकिन इस क्रम में पराली में लगी आग से व्यापक पैमाने पर जो धुआं उठता है, वह आसपास के राज्यों की हवा को बुरी तरह प्रभावित करता है। खासतौर पर हवा का रुख दिल्ली की ओर होने की वजह से राजधानी में प्रदूषण की समस्या बेहद खतरनाक हो जाती है और लोगों के लिए सामान्य रूप से सांस लेना तक दूभर हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली या समूचे एनसीआर में व्यापक प्रदूषण के संकट के लिए अकेले पराली जिम्मेदार है। वाहनों, एयरकंडीशनर आदि से निकलने वाले कार्बन की वजह से हवा बिगड़ने के तथ्य पराली के प्रदूषण के शोर में दब जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि इस गंभीर संकट की अनदेखी के बजाय एक व्यापक कार्ययोजना तैयार हो और उस पर शिद्दत से अमल हो।

तालिबान पर चीन का दांव

ब्रह्मदीप अलूने

चीन अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभाव को लेकर ज्यादा आशंकित है और ऐसे में वह तालिबान के सहारे आइएस को इस इलाके से खदेड़ कर अपने सीमावर्ती प्रांत की शांति को सुनिश्चित करना चाहता है। चीन को डर है कि आतंकी गतिविधियां बढ़ने से इस क्षेत्र में खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए, चीन पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान को सुरक्षा के नाम पर सात करोड़ डालर से ज्यादा की रकम दे चुका है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति को शांति का साधन माना जाता है। कूटनीति ही तर्क, समझौते, वार्ता और लेनदेन की भावना के आधार पर संघर्षों को रोकती है। चीन की कूटनीति बेहद महत्त्वाकांक्षी होकर भी यथार्थवादी है। अफगानिस्तान में खूनी जंग को रोकने के लिए तालिबान से बातचीत के चीन के प्रयास उसकी यथार्थवादी विदेश नीति को प्रतिबिंबित करते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की कवायद के बीच चीन ने बेहद रणनीतिक तरीके से इस मध्य एशियाई देश में शांति के सबसे बड़े अवरोधक तालिबान को बातचीत की मेज पर लाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। एक ओर भारत तालिबान के अस्तित्व को नकारता रहा है, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की सरकार तालिबान को देश की वैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा बताती है और अमेरिका तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्धता दिखाता रहा है। ऐसे में तालिबान को संरक्षण की पाकिस्तान की नीति को चीन द्वारा अपनी कूटनीति का हिस्सा बना लेना इस पूरे महाद्वीप के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

दरअसल, अफगानिस्तान की कबायली संस्कृति मध्य एशिया में बसने वाले कई नृजातीय समूहों के लिए मुफीद है। पश्तून, उज्बेक, ताजिक और हजारा जैसे कबीलों का सांस्कृतिक समन्वय पामीर के पठार से चीन के शिनजियांग प्रांत तक नजर आता है और साम्यवादी चीन के लिए यही स्थिति मुश्किल पैदा करती रही है। चीनी नेताओं का मानना है कि एशिया की समस्त समस्याओं के हल की कुंजी उनके पास है, इसलिए एशिया की किसी भी समस्या का समाधान उसके बिना संभव नहीं है। चीन अपनी विदेश नीति का संचालन बेहद सावधानी से करता है, जिसमें छद्म रूप धारण करके छल का उपयोग किया जाता है। तालिबान को बातचीत की मेज पर लाकर चीन विश्व शांति की दिशा में अपना प्रयास दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी नजरों में उसका उत्तर-पश्चिम का अशांत शिनजियांग प्रांत है। यहां रहने वाले उइगर मुसलमान चीन के खिलाफ पृथकतावादी आंदोलन चला रहे हैं। 'ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट' का मकसद चीन से अलग होना है। यह पृथकतावादी आंदोलन 1949 की स्थिति बहाल करना चाहता है और स्वतंत्र पूर्वी तुर्किस्तान को ही स्वीकार करता है। पूर्वी तुर्किस्तान ही चीन प्रशासित शिनजियांग है। शिनजियांग को एक अलग राष्ट्र के तौर पर कुछ समय के लिए पहचान मिली थी, लेकिन उसी साल इसे चीन का हिस्सा बना दिया गया। इस प्रांत में आंतरिक अशांति इतनी ज्यादा है कि इस साल चीन ने जुलाई मे एक श्वेत पत्र जारी किया था। इसमें कहा गया कि यह अस्थिर प्रांत देश का 'अविभाज्य' हिस्सा है और यह कभी पूर्वी तुर्किस्तान नहीं रहा, जैसा कि अलगाववादी दावा करते हैं।

शिनजियांग की सरहदें दक्षिण में तिब्बत और भारत, पूर्व में मंगोलिया, उत्तर में रूस और पश्चिम में कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं। चीन का सबसे बड़ा संकट शिनजियांग की पश्चिम की वह सीमा है जो मुसलिम देशों से मिलती है और यही कारण है कि चीन अफगानिस्तान में सैन्य अड्डा भी बनाना चाहता है। इसके लिए दोनों देशों के बीच पिछले साल से ही बातचीत शुरू हो चुकी है। चीन ये सैन्य शिविर दूरदराज के पहाड़ी इलाके वाखान कॉरिडोर के पास बनाना चाहता है। यहां पर चीन की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। चीन इस इलाके को प्रभाव में लेकर तुर्किस्तान आंदोलन के प्रभाव को खत्म करना चाहता है। चीन का विश्वास है कि उइगर आतंकी इसी गलियारे से उसके शिनजियांग प्रांत में घुसते हैं। उज्बेक, तुर्कमान और पारसी भाषा बोलने वाले अफगान चीन के वीगर मुसलमानों से आसानी से जुड़ जाते है। पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान में आइएस के उभार से चीन के अशांत शिनजियांग में आंतरिक अशांति और ज्यादा बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

जनवरी 2015 में इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने अपनी खुरासान शाखा स्थापित की थी। खुरासान एक पुराना नाम है जिसके दायरे में अफगानिस्तान और आसपास का इलाका आता है। आइएस ने अरब जगत से बाहर अपने पैर पसारने की कोशिशों के तहत बहुत कम समय में अफगानिस्तान के कम से कम पांच प्रांतों- हेलमंद, जाबुल, फराह, लोगार और नंगरहार में अपनी मौजूदगी का अहसास कराया है। आइएस अफगान तालिबान लड़ाकों को खदेड़ना चाहता है और यह भी चाहता है कि तालिबान-अलकायदा गठबंधन में शामिल लड़ाके उसका हाथ थाम लें। लेकिन स्थानीय समर्थन और राजनीतिक बल हासिल करने की इस कवायद में आइएस को

तालिबान से जबर्दस्त संघर्ष करना पड़ रहा है।

दूसरी ओर, दक्षिण और मध्य एशियाई देशों में सक्रिय आइएस से इस क्षेत्र में सहानुभूति रखने वाले कट्टरपंथी मौजूद हैं। इस क्षेत्र के विभिन्न देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुकर्मेनिस्तान,उज्बेकिस्तान और शिनजियांग से हजारों लड़ाके आइएस के समर्थन में लड़ने के लिए सीरिया और इराक जा चुके हैं। ऐसे में आइएस ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने की कोशिशें जारी रखी हैं, ताकि वह मध्य एशिया, चेचन और चीनी वीगर उग्रवादियों से गठजोड़ कर सके। रूस भी अपनी रणनीति में बदलाव करके पूर्वी अफगानिस्तान में आइएस के उदय को रोकने के लिए तालिबान की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, क्योंकि रूस को डर है कि मध्य एशिया से होते हुए इस्लामिक चरमपंथी हिंसा कहीं उस तक न पहुंच जाए।

यही डर चीन को भी है। चीन वीगरों को आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त बताता है। उसका कहना है कि वीगर अफगानिस्तान जाकर आतंकी प्रशिक्षण लेते हैं और शिनजियांग में अशांति फैलाते हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर हमले के दौरान अमेरिका सेना ने कुछ वीगरों को पकड़ा था। बाद में उन्हें गुआंतानामो खाड़ी जेल में बंदी बना कर रखा गया। चीन अमेरिका में 9/11 के हमले का सहारा लेकर वीगर अलगाववादियों को अधिकाधिक रूप से अलकायदा और आइएस का सहयोगी सिद्ध करने की कोशिश करता रहा है।

चीन अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभाव को लेकर ज्यादा आशंकित है और ऐसे में वह तालिबान के सहारे आइएस को इस इलाके से खदेड़ कर अपने सीमावर्ती प्रांत की शांति को सुनिश्चित करना चाहता है। चीन को डर है कि आतंकी गतिविधियां बढ़ने से इस क्षेत्र में खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए, चीन पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान को सुरक्षा के नाम पर सात करोड़ डालर से ज्यादा की रकम दे चुका है। इतना ही नहीं, चीन अफगानिस्तान को चौवन अरब डालर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में शामिल करने के संकेत भी दे चुका है। चीन तालिबान को सहयोग करके इस समूचे इलाके में रहस्यमय वातावरण तैयार कर समस्या को और जटिल बना सकता है। चीन की विदेश नीति का सैद्धांतिक पक्ष राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा है। चीन चाहता है कि एशिया से सभी पश्चिमी शक्तियों को निकाल दिया जाए। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि वह भारत को इस क्षेत्र में शक्तिशाली होने से रोकना है। चीन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों और तरीकों का प्रयोग करता है, वे अत्यंत खतरनाक है।

भारत-ईरान और अफगानिस्तान सहयोग भी पाकिस्तान और चीन के लिए रणनीतिक चिंता का कारण है। चाबहार और उत्तर दक्षिण पारगमन गलियारे का उद्देश्य अफगानिस्तान और मध्य एशिया क्षेत्र के देशों के साथ संपर्क बढ़ाना है। बदलते दौर में सामरिक और सुरक्षा प्राथमिकताएं बदली हैं। तालिबान के परंपरागत शत्रु रूस ने तालिबान से वार्ता की है, यहां तक कि रूस पर तालिबान को आइएस से लड़ने के लिए हथियार देने के भी आरोप लगे है। ईरान, रूस, अमेरिका, चीन और उज्बेकिस्तान जैसे देश भी तालिबान से बात कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए परंपरागत अफगान नीति से आगे बढ़ कर अग्रगामी कदम उठाते हुए तालिबान से बातचीत के द्वार खोलना राष्ट्रीय हित में होगा। कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए भी तालिबान की तटस्थ भूमिका भारत के लिए जरूरी है।

प्याज का संकट

प्याज के दाम एक बार फिर सौ रुपए किलो से ऊपर निकल गए हैं। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, कई शहरों में इन दिनों प्याज लोगों के आंसू निकाल रहा है। सवा-डेढ़ महीने पहले भी प्याज अस्सी-नब्बे रुपए किलो तक बिका था। तब दाम काबू करने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार तक ने कई कदम उठाने के वादे-दावे किए गए थे। कुछ दिन तो राहत मिली, लेकिन फिर से प्याज के दाम सौ रुपए से भी ऊपर चले गए। इसका मतलब है कि इस कारोबार पर सरकार की कोई लगाम नहीं है और व्यापारी अपने हिसाब से चल रहे हैं। यह कोई एकाध साल की बात भी नहीं है, बल्कि साल में एक-दो बार ऐसा झटका गरीब की जेब पर लग ही जाता है। दिल्ली की मंडियों में पिछले एक हफ्ते के दौरान प्याज के दामों में पैंतालीस फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और थोक भाव अस्सी रुपए तक जा पहुंचा। इसका असर यह हुआ कि मंडियों से बाजार तक पहुंचने में खुदरा भाव सौ रुपए किलो तक पहुंच गया। यह चिंता और परेशानी की बात ज्यादा इसलिए है कि प्याज रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है। लेकिन सरकारें बेफिक्र हैं, उन्हें प्याज के दाम बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हालत यह है कि इस साल प्याज के दाम पिछले चार साल में सबसे ज्यादा चढ़े हैं।

आखिर क्या कारण है कि महीने-दो महीने भी नहीं गुजरते और प्याज के दाम आसमान छू जाते हैं? मोटे तौर पर तो इसे प्याज की फसल से जोड़ कर देखा जाता है। अभी तात्कालिक कारण यह बताया जा रहा है कि बेमौसम की बारिश से प्याज की फसल पर बुरा असर पड़ा है, इसलिए जिन राज्यों से समय पर मंडियों में प्याज पहुंचना था, वह पहुंच नहीं पाया और अचानक से कमी हो गई और दाम चढ़ गए। राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक से दिल्ली सहित कई शहरों में प्याज की भारी मात्रा में आपूर्ति होती है। लेकिन इन दिनों दिल्ली सहित कई शहरों की मंडियों में प्याज की आवक चालीस-पचास फीसद तक घट गई है। दीपावली के महीने भर पहले भी प्याज ने इसी तरह रुलाया था। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव (महाराष्ट्र) में तब भी प्याज के दाम साठ रुपए किलो बिक रहा था और आज भी यही है। लेकिन अब तो खुदरा भावों ने डेढ़ महीने पहले का रिकार्ड तोड़ डाला है।

प्याज के बढ़ते दामों का संकट आम लोगों के लिए हैं, सरकार के लिए नहीं। व्यापारी इसे कुछ ही समय का संकट बता रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि जब प्याज की फसल खराब होती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जमाखोर उठाते हैं, वे अपना स्टाक मनमानी कीमत पर निकालते हैं और सीधे खुदरा बाजार में बेचते हैं। लेकिन सरकार जमाखोरों पर अंकुश कभी नहीं लगा पाती। एकाध-दो व्यापारियों पर छापे मार कर कार्रवाई की औपचारिकता कर दी जाती है। यह सिलसिला हर साल का है। दिल्ली में हालांकि सरकार ने सरकारी बिक्री केंद्रों पर सस्ता प्याज मिलने के दावे किए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन केंद्रों पर प्याज है नहीं। लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। सवाल यह है कि जब मालूम है कि प्याज का संकट कभी भी खड़ा हो सकता है तो इस समस्या स निपटने के उपाय पहले से क्यों नहीं किए जाते? क्यों राज्य सरकारों और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के बीच तालमेल नहीं है? तब प्याज का जमा स्टॉक कहां चला जाता है? अगर ऐसे संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी हो तो लोगों के आंसू तो नहीं निकलें!

कल्पमेधा

डॉक्टर मृत्यु तक विद्यार्थी रहता है और जब वह विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देता है तो उसकी मृत्यु समझो।

- लार्ड डासन

पेड़ का जीवन

सुरेशचंद्र रोहरा

सड़क के किनारे उच्च मार्ग पर 'गंगा इमली' के करीब दो दर्जन पेड़ हैं। ये हमें सदैव आकर्षित करने वाले मीठे-मीठे फल, औषधि के रूप में अपनी पत्ती, तने देने वाले, हृदय को आह्लादित करने वाले गंगा इमली के पेड़ आने वाले दिनों में जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। जिस वक्त यह जानकारी मिली, मेरा हृदय हाहाकार कर उठा। हमारे शहर के उपनगर दर्री से कटघोरा मार्ग पर देश की एक कंपनी की 2100 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर देश को रोशन करने वाले सयंत्र के साथ एक बड़ी कॉलोनी है। इस कॉलोनी की चारदिवारी के बाहर जंगल-जलेबी के लगभग दो दर्जन अनमोल वृक्ष खड़े हैं, जो भरपूर फल देते हैं। जाने किसने उन्हें कब रोपा है, लेकिन आज वे विशाल वृक्ष छांव के साथ फल देते हैं। मगर नेशनल हाइवे की चार लेन वाली सड़क अब इन वृक्षों अपना ग्रास बना लेगी। यह दुखद सच अब आंखों और मनोमस्तिष्क के आगे दुःस्वप्न बन कर तैरने लगता है तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। सोचता हूं कि क्या सच में हम इतने कठोर हैं? हमारी व्यवस्था इतनी असंवेदनशील क्यों है? क्यों उसे दिखाई नहीं देता कि जो वृक्ष वर्षों से खड़े हैं, हम उन्हें इतनी बेदर्दी से काट देते हैं!

मैंने हाल ही में झारखंड के रांची के पास उरगा-हाटी मार्ग और उत्तर प्रदेश में कटघोरा-अंबिकापुर में विशाल वृक्षों को सड़क निर्माण में खेत होते देखा है। चार लेन सड़क निर्माण के नाम पर छत्तीसगढ़ में सैकड़ों वृक्षों को बेरहमी से काट दिया गया। छत्तीसगढ़ बौद्धिक सामाजिक और संवेदनशील लोगों का राज्य माना जाता है। मगर यह देख-सुन कर कोफ्त होती है कि पेड़ों को काटे जाने का कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। मैं जब इस मार्ग पर निकलता और पेड़ों को जमींदोज देखता तो हृदय हाहाकार करने लगता... आंखों में आंसू भर आते। सत्ता कितनी असंवेदनशील है, यह सोच मन में जुगुप्सा भर आती है। लगता है जब कहीं कोई रोशनी नहीं है, अंधियारा फैला है।

दुनिया मेरे आगे

मन में सवाल उठता है कि तब तुम क्यों आगे नहीं आते? मैं या मुझ जैसे लोग हों जो इसका प्रतिकार पुरजोर शब्दों में करें, लिखें या फिर आंदोलन करें। पेड़ काटा जाए तो 'चिपको आंदोलन' के प्रणेता से प्रेरणा लेकर विरोध करें, उसे बचाने के लिए लिपट जाएं। मगर ऐसा कोई नहीं है! मैं भी नहीं कर सका... बस देखता रहा... खुद को अपराधी महसूस करते हुए। हां, तब सत्ता प्रतिष्ठान के लिए मुंह से बरबस आह जरूर निकली थी! हिंदी के बड़े संपादक रहे धर्मवीर भारती की पत्नी पुष्पा भारती ने एक करुण लेख लिखा था। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जिस दिन धर्मवीर भारती का निधन हुआ था, उसी रात उनके घर के निकट एक बड़े वृक्ष का बड़ा हिस्सा बिना तूफान, पानी, हवाओं के टूट कर गिर पड़ा था। भारती जी ने घर पर जाने कितने पौधे, वृक्ष लगा रखे थे और उनसे बतियाते रहते थे।

वृक्षों के हमारे लिए जरूरी होने के जाने कितने तर्क हैं। यह हम अक्सर बताते रहते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई के पास आरे में लोगों ने पेड़ों को काटे जाने का जिस तरह विरोध किया, वह मेरे लिए आश्वस्ति की खबर रही। ये पेड़ जो हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य हैं, समाचार माध्यमों में कभी-कभार मुख्य मुद्दा बनते रहते हैं। मगर सच यह है कि एक-दो अपवादों को छोड़ कर हमारे आसपास वृक्ष काटे जा रहे हैं। जंगल में कीमती लकड़ियों के लिए तस्कर वन माफिया बदस्तूर अपना काम कर रहा है। कई बार खुद वन कर्मी इन्हें संरक्षण देते हैं। हम घर के आसपास लगे वृक्षों को अपनी क्षुद्र आवश्यकता और स्वार्थ के कारण काट देते हैं। ऐसे में विवेकशील संवेदना से भरपूर चंद लोग ही हैं जो इस मसले पर सकारात्मक रुख रखते हैं और कभी-कभी सुकून भरी खबरें सुर्खियां बन कर लोगों को, हमको प्रेरणा देते हैं।

रही बात जंगल जलेबी की, तो यह रहस्यमयी मीठे-मीठे फलों का उत्स आजकल साहित्य की दुनिया में आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि अब शहरों में यह लुप्तप्राय है। जिन्होंने बचपन में एक दफे इसका स्वाद चखा है, देखा है, वे इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। मगर अब संभव नहीं हो पाता। 'जंगल जलेबी' शीर्षक से मशहूर लेखिका नासिरा शर्मा की एक रोचक कहानी है जो बच्चों को जंगल जलेबी के संदर्भ में ढेर सारा ज्ञान देती है।

हमारे मोहल्ले में जंगल जलेबी के आठ-दस वृक्ष हुआ करते थे। बचपन में हम फल तोड़ते और खूब आनंद विभोर होते। अब सिर्फ एक वृक्ष बचा है। हाइवे की चपेट में आने वाले लगभग दो दर्जन वृक्षों के प्रति मैं अतिशय चिंतित हूं। क्या ये वृक्ष बेदर्दी से काट डाले जाएंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चाहें हम जैसा भी करें, वृक्ष न कटे कम से कम! एक साथ खड़े ये वृक्ष जो जाने कैसे, किसने रोपे होंगे, क्या सोचा होगा? कितने वर्ष व्यतीत हो गए, आज फल दे रहे हैं, मगर हम कृतघ्न हैं। अच्छा हो, सरकार वृक्षों को जड़ समेत निकाल कर कहीं दूर रोप दे..! यह तकनीक विदेशों में है। फिर हम क्यों पीछे हैं?

जासूसी का जाल

अभिव्यक्ति और निजता के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर तरह-तरह की आशंकाओं के बीच ताजा वाट्सऐप जासूसी का चौंकाने वाला खुलासा बेहद चिंता पैदा करने वाला है। दुनियाभर में करीब डेढ़ अरब लोग वाट्सऐप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यह हमले खास लोगों को निशाना बना कर किए गए थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इजरायली कंपनी में बने सॉफ्टवेयर से वाट्सऐप में सेंध लगा कर भारतीय पत्रकारों, वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी के मामले में कई खुलासे हुए हैं। विपक्ष ने तो इसे मुद्दा बनाया ही है, सरकार के लिए भी यह चिंता का विषय होना चाहिए। फोन और मोबाइल पर बातचीत टेप करने के वैध और अवैध उदाहरण तो लगातार आते ही रहे हैं और इनमें सरकारी एजेंसियों की भागीदारी भी रही है। सरकारी एजेंसियां अमूमन इसे देशहित में आतंकी और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिहाज से जायज ठहराती रही हैं। अदालतें हालांकि बार-बार हिदायत देती रही हैं कि इसके बहाने व्यक्ति की अभिव्यक्ति और निजता के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ऐसे दौर में वाट्सऐप भरोसा दिलाता रहा है कि उस पर की गई बातचीत या भेजे गए मैसेज सुरक्षित हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाइवेयर पेगासस के जरिये व्हाट्सएप की बातचीत और संदेशों को टेप किया जाता रहा है।

दिलचस्प वाली बात यह है कि नागरिकों की निजता पर हुए हमले की सूचना हमें तब मिली जब खुद वाट्सऐप ने अमेरिका में इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए बताया कि इस कंपनी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर के जरिए दुनियाभर में 1400 लोगों के फोन से सूचनाएं उड़ाई गई हैं। फेसबुक के स्वामित्व वाले संदेश भेजने के प्लेटफार्म वाट्सऐप ने कहा है कि भारत में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर पेगासस के जरिये नजर रखी जा रही थी। यह नजर कौन किसलिए रखेगा इसे समझना मुश्किल नहीं है और अगर ऐसा हुआ है तो यह हमारी सुरक्षा के ख्याल रखने वालों (यानी सरकार) की चूक है। व्हाट्सएप ने भी कहा है कि संबंधित लोगों को जासूसी की सूचना दी है।

सवाल उठता है कि अगर बौद्धिक पत्रकारों या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की भी निजता और अभिव्यक्ति की आजादी भी सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या होगा। हालांकि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़े फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखते हुए आधार के इस्तेमाल को सिर्फ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित कर दिया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे अधिकारों का हनन न हो यह देखना भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी तक सरकार की ओर से कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं आया है। सरकार को स्पष्ट शब्दों में अपने पर लग रहे आरोपों और शक की सुई उनकी तरफ घूमने पर जवाब देना ही होगा।

● *अमन सिंह, बरेली*

किसान दोषी क्यों

आज एक स्वर में पूरे देश में पराली जलाने को लेकर केवल किसान के ऊपर जिस तरीके से दोषारोपण किया जा रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखी कर देने वाली स्थिति है। जो किसान रात-दिन मेहनत करके सबका पेट भरता है, क्या उसके बारे में कभी किसी ने सोचा है कि उसको उसकी फसल का वाजिब मूल्य भी मिल पाता है या नहीं और नहीं मिल पा रहा है तो क्यों? न उसके पास फसल कटवाने के लिए कामगार है, न ही पराली की अलग से व्यवस्था करने के लिए धन, न ही पराली नष्ट करने का विकल्प उसके सामने है। क्या सीधे-सीधे पूरी व्यवस्था इसके लिए दोषी नहीं है। पहला काम सरकार को यह करना चाहिए कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो और उन से चर्चा करके इस संबंध में एक उचित और दीर्घकालिक नीति बनाने की कोशिश करें, ताकि प्रदूषण को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय को बार-बार निर्देश ना देना पड़े।

● *रमेश माहेश्वरी, सुल्तानपुर*

खतरे का संकेत

पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। साथ ही धरती का वातावरण गंभीर प्रदूषण का भी सामना कर रहा है। समुद्र भी प्रदूषण से अछूते नहीं रह गए हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि धरती पर प्राणी जगत के अस्तित्व पर खतरा खड़ा हो गया है। लोगों की औसत आयु भी कम होती जा रही है। हाल में थाईलैंड की राजधानी बैंकाक मे मीडिया को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने दुनियाभर में समुद्रों के बढ़ते जलस्तर पर चिंता जाहिर करते हुए भारत, जापान, चीन और बांग्लादेश को आगाह करते हुऐ इस संकट से निपटने के लिए कहा है और अभी तक इससे निपटने के लिए जो काम हो रहेहैं उन्हें नाकाफी बताया है। यदि समय रहते हम सचेत नहीं हुए तो भारत के साथ ही दुनिया के कई शहर समुद्र में डूब सकते हैं।

● *संजय डागा, हातोद*

हिंसा और सवाल

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में एक वकील की गाड़ी पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद, पहले गिरफ्तारी, फिर हिंसक झड़प और बाद में सड़क पर खुली लड़ाई तक पहुंच गया। क्या केवल गाड़ी पार्किंग को लेकर वकीलों का इस तरह हिंसा पर उतर आने को किसी भी रूप से उचित कहा जा सकता है? भिड़ंत के बीच दिल्ली पुलिस की ओर से फायरिंग भी की गई, जिसमें दो वकील घायल हो गए। क्या पुलिस फायरिंग न करके और कोई दूसरा कदम नहीं उठा सकती थी? दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच भड़की हिंसा का असर यह हुआ कि कानपुर में भी एक वकील ने पुलिस जवान की पिटाई कर दी। समझने वाली बात है कि समाज को कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस और वकील यदि इस तरह की गुंडागर्दी और मारपीट पर उतर आएंगे तो आखिर न्याय के लिए खड़ा कौन होगा? सबसे बुरी बात तो यह रही कि पढ़े-लिखे वकील समुदाय ने जो संविधान और कानून की शपथ लेते हैं और जनता की रक्षा और उसे न्याय दिलाने का संकल्प लेते हैं, उन्हीं वकीलों ने आम लोगों को भी नहीं बक्शा, राह चलते लोगों को जमकर पीटा, ऑटो वाले को पीट कर घायल कर दिया। न्याय मित्रों से समाज को बहुत अपेक्षाएं रहती हैं। परिस्थिति कितनी ही विकट हो, धैर्य व संयम से काम लेना चाहिए।

● *मंगलेश सोनी, मनावर, धार*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com